

(b) The scheme comprises the construction of breakwaters and certain river training works.

(c) No.

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकों गुम होना

3016. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से अनेक पुस्तकें गुम हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सबन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री० एस० नुबल हसन) : (क) से (ग) . बनारस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1972 में पुस्तकालय के कुछ अनुभागों की जांच परख की गई थी जिसमें विश्वविद्यालय ने पाया कि कुछ पुस्तकें ली गई हैं जो कि सामान्य प्रीसत से बहुत ज्यादा हैं। विश्वविद्यालय का अगले प्रीसतकालीन आचकाश में सारे पुस्तकालय के स्टॉक की व्यापक जांच करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही सही मुकदमा का पता चकेगा।

मध्य प्रदेश द्वारा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों की मांग

3017. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश को जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आयात किये गये कितने ट्रैक्टरों की सप्लाई की गई,

(ख) क्या इस अवधि के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक ट्रैक्टरों की मांग की है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्डे) : (क). वर्ष 1969-70 की अवधि में पूर्वी जर्मनी से 1998 भार.एस.-09 ट्रैक्टर आयात किये गये थे। मध्य प्रदेश को भार.एस.-09 ट्रैक्टरों का कोई आवंटन नहीं किया गया।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से भार.एस.-09 ट्रैक्टरों की और आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारत में पुस्तकों के प्रकाशक और पाठक

3018. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में पुस्तकों के प्रकाशक और पाठक कम हैं ;

(क) ' यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और "

(ग) स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति मंत्रों (प्रो० ए०० नुल्ल हसन): (क) से (ग). विभिन्न देशों में प्रकाशकों और पाठकों की संख्या से सम्बन्धित किसी प्रकार के आकड़ों के अभाव में कोई तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है ।

2. तथापि जो कुछ मालूम हुआ है वह यह कि भारत, एशिया और यूरोप प्रति दस लाख की जन संख्या के लिये प्रति वर्ष क्रमशः 22 पुस्तकें, 32 पुस्तकें और 418 पुस्तकें तैयार करते हैं । किन्तु यह मान लिया गया है कि पुस्तक उत्पादन में एशिया में भारत का दूसरा (इसमें चीन गणतंत्र के आकड़े नहीं लिये गये हैं । क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हैं), और विश्व में उसका आठवां स्थान है । जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रति व्यक्ति पुस्तकों का निर्माण यह व्यक्त करता है कि पुस्तक निर्माण के कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर विस्तार की गुंजाइश है । पुस्तकों के प्रसार हेतु और अध्ययन की भावना को डालने के लिये लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन, सस्ते पेपर बैक संस्करणों के उत्पादन और स्कूल व कॉलेज स्तरों आदि की सहायता प्राप्त पाठ्य-पुस्तकें इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं । पुस्तक निर्माण कार्य का विस्तार देश के आम औद्योगिक विस्तार से भी सम्बन्धित है ।

**Central Subsidy to Cashewnut
Producing States**

3019. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Central Government are giving subsidy to different Cashew nut producing States for its increased production so that its exports may earn more foreign exchange;

(b) if so, whether Government will extend similar financial assistance to Cashew nut cultivators in the Contal Sub-division of Midnapur District of West Bengal, and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE
(SHRI ANNASAHEB P SHINDE)**

(a) Yes, Sir, Government of India are giving assistance to the States on the following terms :

- (i) A subsidy of 200, paise, on each Cashew nut layer
- (ii) A subsidy of Rs 25/- per acre on plot protection chemicals.
- (iii) A subsidy of Rs 300/- per plot of 2 acres each for demonstration plots
- (iv) Expenditure on staff under the schemes on production of cashew nut layers and adoption of plant protection measures as also for the schemes on Marketing Surveys.

(b) and (c) During 1971-72 the Government of India have provided assistance to the West Bengal Government for organising demonstrations in areas including Contal Sub-division for educating the farmers in the improved methods of cultivation. The State Government have not, however, claimed assistance under other items. The assistance will be extended as and when the State Government submits a proper scheme.